



भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश: अवसर, भ्रम या समय के विरुद्ध दौड़?

अभिनव कुमार सरोज*

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226007

लेखक से संवाद के लिए ईमेल: abhipas0110@gmail.com

आलेख प्राप्त: २६ अगस्त २०२६; अंतिम संशोधन: १० अक्टूबर २०२६; स्वीकृत: १० अक्टूबर २०२६

प्रथम ऑनलाइन प्रकाशित: १० अक्टूबर २०२६

सारांश

भारत की बदलती आयु-संरचना को अक्सर उसके अगले चरण के आर्थिक विकास का बड़ा आधार माना जाता है। घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा ने भारत में कार्यशील आयु वाली जनसंख्या की हिस्सेदारी बढ़ाई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश लगभग 2030 के आसपास अपने चरम पर पहुँच सकता है, जब 15-59 वर्ष आयु वर्ग की आबादी लगभग 65 वर्ष होगी। लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश केवल युवा आबादी की मौजूदगी से पैदा नहीं होता उसका आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उस आबादी को कितनी प्रभावी ढंग से शिक्षा, कौशल और उत्पादक रोजगार से जोड़ा जाता है। यह लेख भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को तीन प्रश्नों के माध्यम से देखता है— क्या यह वास्तविक अवसर है, क्या इसकी चर्चा में अतिशयोक्ति का तत्व है, और क्या भारत के पास इसे हासिल करने के लिए सीमित समय है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के श्रम-बाजार संकेतकों, भारत के जनसांख्यिकीय अनुमानों और उपलब्ध अनुभवजन्य साहित्य के आधार पर लेख तर्क देता है कि भारत के सामने अवसर वास्तविक है, लेकिन उसका परिणाम स्वतः सुनिश्चित नहीं है। विशेष रूप से महिला श्रम-बल भागीदारी, रोजगार की गुणवत्ता और राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय अंतर इस अवसर की वास्तविक आर्थिक कीमत तय करेंगे।

प्रमुख शब्द: जनसांख्यिकीय लाभांश, कार्यशील आयु जनसंख्या, रोजगार, महिला श्रम-बल भागीदारी, मानव पूंजी, वृद्धावस्था



India's Demographic Dividend: Opportunity, Illusion, or A Race Against Time?

Abhinav Kumar Saroj*

Department of Economics, University of Lucknow, Uttar Pradesh

Corresponding Author Email- abhipas0110@gmail.com

Received on: 29 August 2026; Final Revision: 10 October 2026; Accepted: 10 October 2026

Published Online First on: 10 October 2026

ABSTRACT:

India's changing age structure is widely regarded as a major source of potential economic growth. Declining fertility and increasing life expectancy have raised the share of the working-age population, creating conditions for a demographic dividend. According to the Economic Survey 2025–26, India's demographic dividend is expected to approach its peak around 2030, with the population aged 15–59 years projected to account for about 65% of the population. However, demographic change by itself does not generate economic growth; its benefits depend on the effective integration of the working age population into productive employment. This paper examines India's demographic dividend as an opportunity, a potential illusion, and a timebound economic window. Drawing on evidence from the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2025, demographic projections and existing empirical literature, it examines labour force participation, female economic participation, employment quality, and differences in demographic transition across Indian states. The evidence suggests that India possesses a genuine demographic opportunity, but its conversion into sustained economic gains is not automatic. Low female labour-force participation, the need for more productive employment, differences across states, and the emerging challenge of population ageing are central to determining the extent of the dividend. The paper argues that India's demographic advantage should therefore be viewed not simply as a consequence of having a young population, but as a time-bound opportunity that depends on human capital, productive employment and labour-market participation.

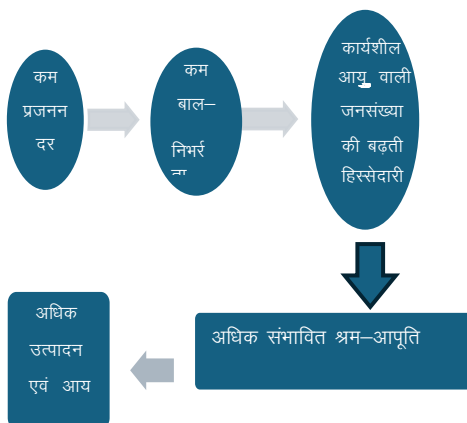
Keywords: Demographic dividend, Working Force Population, Employment, Female Participation Rate, Human capital, Old Age Problem

1. प्रस्तावना

किसी देश की जनसंख्या केवल उसकी संख्या नहीं होती उसकी आयु संरचना भी आर्थिक परिणामों को प्रभावित करती है। जब जन्मदर घटती है और जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, तो आश्रित आबादी की तुलना में कार्यशील आयु वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। यही वह स्थिति है जिसमें जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना पैदा होती है। भारत इसी परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 15-59 वर्ष आयु वर्ग की आबादी की हिस्सेदारी लगभग 2030 में 65 प्रतिशत के आसपास चरम पर पहुँचने की उम्मीद है लेकिन इसी के साथ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जा चुकी है। और जनसंख्या की वृद्धावस्था की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की असली चुनौती सामने आती है। बड़ी कार्यशील आयु वाली आबादी अपने आप सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ाती। उसे श्रम-बल में शामिल होना होगा, रोजगार मिलना होगा और उस रोजगार की उत्पादकता पर्याप्त होनी होगी। इसीलिए भारत के सामने प्रश्न यह नहीं है कि उसके पास युवा आबादी है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या वह युवा आबादी को आर्थिक शक्ति में बदल सकता है?

2. जनसांख्यिकीय लाभांश: अवसर की अर्थव्यवस्था

जनसांख्यिकीय लाभांश का मूल आर्थिक तंत्र सरल है। इसके साथ बचत और निवेश के माध्यम से दूसरा मार्ग भी काम कर सकता है। अधिक कार्यशील आयु वाली जनसंख्या और घरेलू आय में वृद्धि से बचत बढ़ सकती है, जिन्हें निवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। अख्यर और मोदी (2011) का भारतीय राज्यों पर किया गया अनुभवजन्य अध्ययन महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि कार्यशील आयु अनुपात के स्तर और उसकी वृद्धि, दोनों का प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।



चित्र 1 – जनसांख्यिकीय लाभांश का आर्थिक तंत्र

उनके अनुमान के अनुसार 1970 के दशक से भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का 40-50 प्रतिशत तक जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ा हो सकता था। यह एक ऐतिहासिक अर्थमितीय अनुमान है जिसे आज की वृद्धि का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। इस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि जनसांख्यिकीय आर्थिक विकास के लिए केवल पृष्ठभूमि चर नहीं हैं वह वृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

3. जनसांख्यिकीय लाभांश की पहली परीक्षा :रोजगार –

कार्यशील आयु वाली जनसंख्या तभी आर्थिक परिसंपत्ति बनती है जब वह श्रम-बाजार में उत्पादक रूप से जुड़ती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी की श्रम बल भागीदारी दर 59.3 प्रतिशत थी। पुरुष श्रम बल भागीदारी दर 79.1 प्रतिशत, जबकि महिला श्रम बल भागीदारी दर 40.0 प्रतिशत थी। 15-29 वर्ष के युवाओं में कुल दर 46.0 प्रतिशत थी पुरुषों के लिए 64.0 प्रतिशत और महिलाओं के लिए केवल 27.5 प्रतिशत। आँकड़े यह नहीं बताते कि जनसांख्यिकीय लाभांश विफल हो चुका है लेकिन वे यह जरूर दिखाते हैं कि कार्यशील आयु वाली जनसंख्या और आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या एक ही चीज नहीं हैं। विशेष रूप से युवा महिलाओं की कम श्रम-बल भागीदारी भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता और उसके वास्तविक आर्थिक उपयोग के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है।

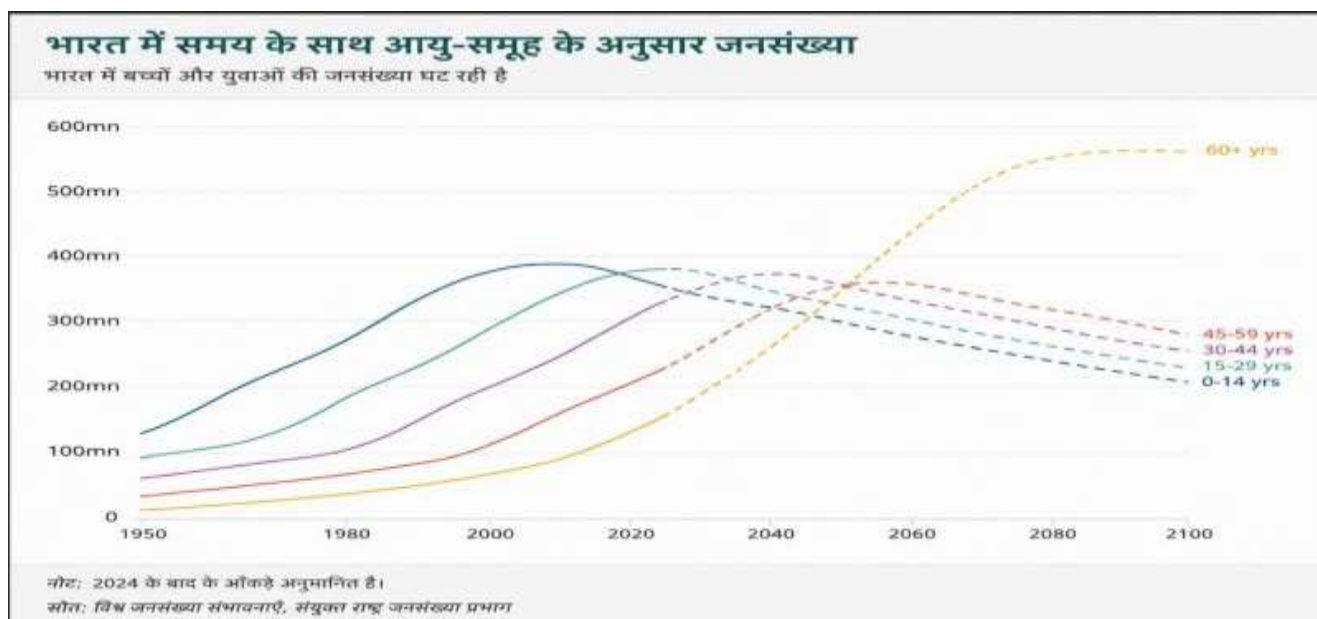
4. महिला श्रम-बल भागीदारी: छूटा हुआ लाभांश –

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर चर्चा पुरुष और महिला दोनों की उत्पादक क्षमता को समान महत्व दिए बिना अधूरी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं की जबकि शहरी क्षेत्रों में 27.7 प्रतिशत थी। पुरुषों में यही दर क्रमशः 80.5 प्रतिशत और 76.2 प्रतिशत थी। यह अंतर केवल श्रम-बाजार का आँकड़ा नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत की बड़ी कार्यशील आयु वाली महिला आबादी का एक हिस्सा अभी श्रम-बाजार में शामिल नहीं है।

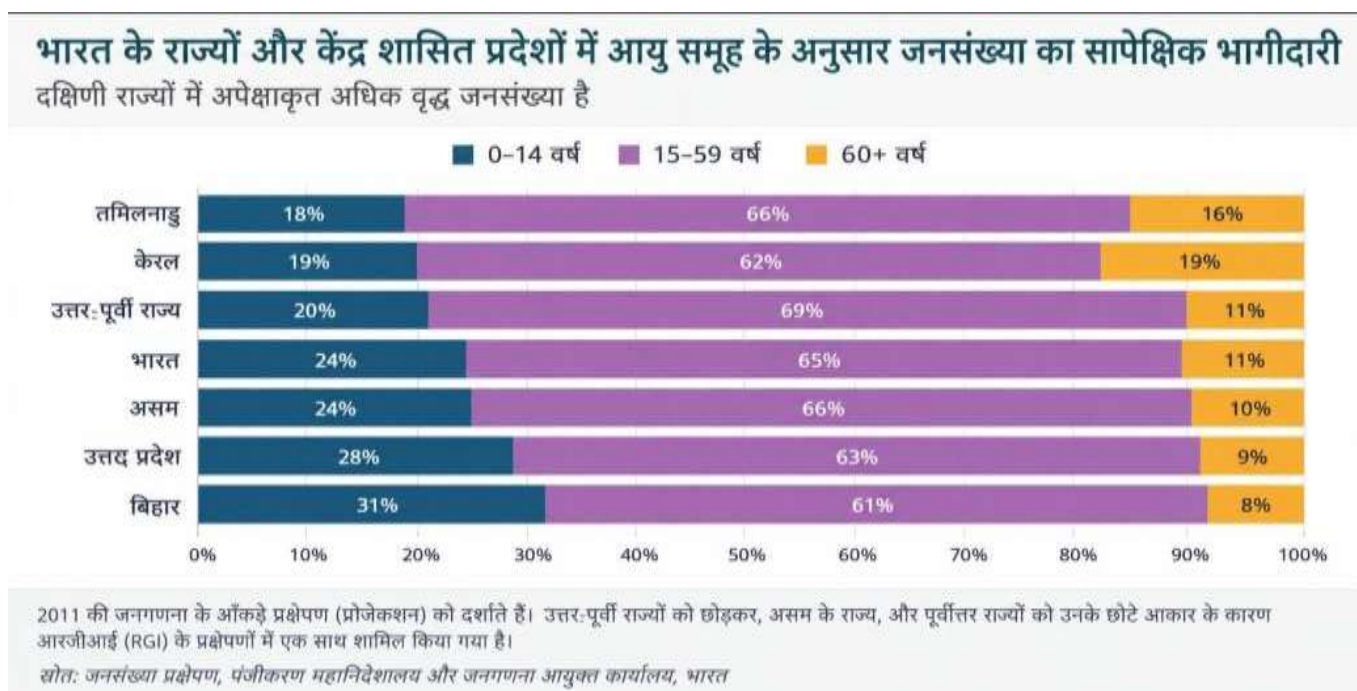
हालाँकि इसे सीधे 'अप्रयुक्त श्रम' कहना भी उचित नहीं होगा। महिलाओं का अवैतनिक घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और अन्य घरेलू जिम्मेदारियाँ बाजार-आधारित रोजगार आँकड़ों में पूरी तरह दर्ज नहीं होतीं। फिर भी, यदि भारत बाल-देखभाल, सुरक्षित आवागमन, उपयुक्त कौशल, लचीली कार्य-व्यवस्था और उपयुक्त रोजगार अवसर जैसी बाधाओं को कम कर सके, तो महिला आर्थिक भागीदारी जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्वपूर्ण अतिरिक्त मार्ग बन सकती है।

5. रोजगार की संख्या से आगे: रोजगार की गुणवत्ता–

जनसांख्यिकीय लाभांश की दूसरी चुनौती रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार सामान्य स्थिति में नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी 2024 के 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 23.6 प्रतिशत हुई। इसी अवधि में विनिर्माण में श्रमिकों की हिस्सेदारी में व्यापक रूप से वृद्धि और कृषि में कमी दर्ज की गई। यह परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन केवल रोजगार की स्थिति से उत्पादकता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। भारत के लिए वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए– अधिक लोगों को काम देना ही नहीं, बल्कि अधिक लोगों को अधिक उत्पादक काम से जोड़ना। यही वह बिंदु है जहाँ कौशल, शिक्षा और औद्योगिक संरचना जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ते हैं।



चित्र 2 – भारत में समय के साथ विभिन्न आयु-वर्गों की जनसंख्या का अनुमानित परिवर्तन (1950–2100)



चित्र 3– भारत के चयनित राज्यों में आयु-वर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण (2011 की जनगणना के आधार पर प्रक्षेपण)

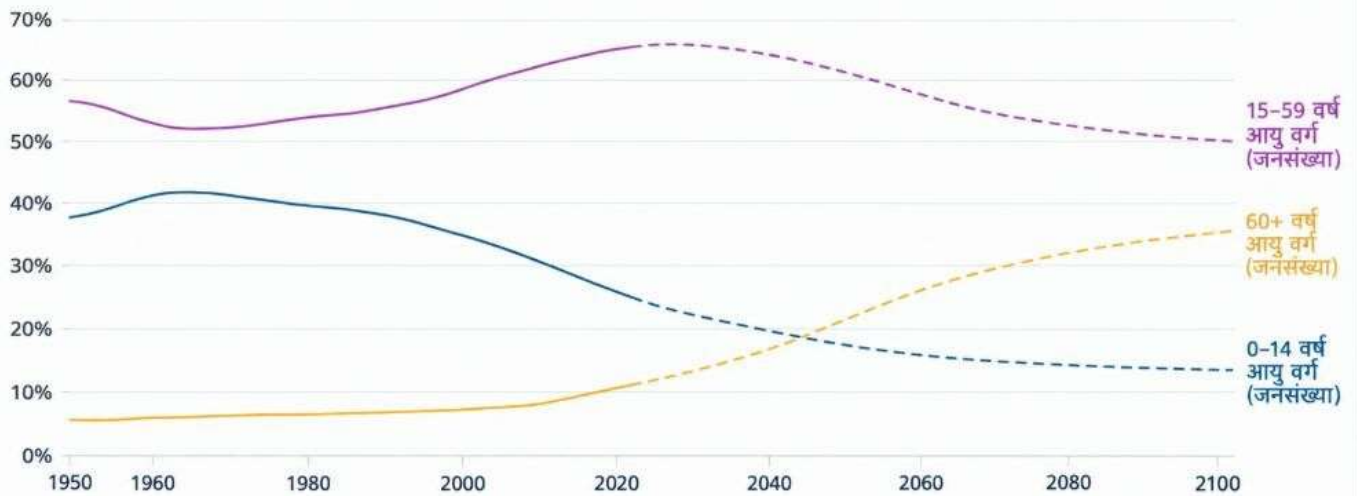
6. क्या जनसांख्यिकीय लाभांश सभी राज्यों के लिए समान है?

भारत की जनसांख्यिकीय कहानी को राष्ट्रीय औसत से समझना पर्याप्त नहीं है। अख्यर और मोदी के ऐतिहासिक राज्य-स्तरीय विश्लेषण में तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में कार्यशील आयु अनुपात के अनुकूल बदलाव और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के बीच मजबूत संबंध दिखाई दिया, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनसांख्यिकीय संक्रमण अपेक्षाकृत बाद में आया। अध्ययन में 1980 और 1990 के दशकों के दौरान जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभाव राज्यों के बीच काफी अलग था। (चित्र 3 देखें)

इसका समकालीन नीतिगत अर्थ महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों में जनसांख्यिकीय संक्रमण अभी अपेक्षाकृत शुरुआती अवस्था में है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार सृजन पर जोर अधिक जरूरी है। जिन राज्यों में वृद्धावस्था तेजी से बढ़ रही है, वहाँ स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, वृद्ध देखभाल और उत्पादकता की चुनौती अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तव में एक राष्ट्रीय अवसर के भीतर कई अलग-अलग राज्य-स्तरीय अवसर-खिड़कियों का समूह है।

भारत की जनसांख्यिकीय खिड़की बंद हो रही है

भारत की कार्यशील आयु समूह (15-59 वर्ष) की जनसंख्या का अनुपात अपने चरम पर पहुँचने के बाद घटने लगा है



2024 के बाद के आंकड़े पूर्वानुमानों पर आधारित हैं।

स्रोत: वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग

चित्र 4- भारत की बदलती आयु-संरचना और जनसांख्यिकीय संक्रमण

7. अवसर की समय-सीमा-

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को समझने में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शायद यही है—यह अवसर कितने समय तक रहेगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश लगभग 2030 में चरम पर पहुँचने की उम्मीद है। उसी समय वृद्धावस्था का महत्व बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' के अनुसार 2050 तक भारत की 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। 2046 के आसपास वृद्ध आबादी बच्चों की आबादी से अधिक होने की संभावना भी बताई गई है। इसलिए जनसांख्यिकीय संक्रमण को केवल 'युवा भारत' की कहानी मानना अधूरा होगा। भारत जिस कार्यशील आयु वाली आबादी को आज आर्थिक परिसंपत्ति मान रहा है, वही आने वाले दशकों में वृद्ध आबादी का आधार बनेगी। यही कारण है कि जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तव में एक समयबद्ध अवसर है।

8. अवसर या भ्रम?

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर वास्तविक है, क्योंकि कार्यशील आयु वाली आबादी की संरचना अनुकूल है और अनुभवजन्य साक्ष्य जनसांख्यिकीय संरचना तथा आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध दिखाते हैं। लेकिन यह भ्रम बन सकता है यदि कार्यशील आयु वाली आबादी उत्पादक रोजगार में समाहित न हो, कौशल और श्रम-बाजार की मांग में अंतर बना रहे, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कम रहे और राज्यों के जनसांख्यिकीय अंतर को नीतियों में नजरअंदाज किया जाए। और यह समय के विरुद्ध दौड़ है क्योंकि अनुकूल आयु-संरचना स्थायी नहीं है। लगभग 2030 का अनुमानित चरम और उसके बाद बढ़ती वृद्धावस्था बताती है कि जनसांख्यिकीय अवसर को अनिश्चित भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता।

9. नीतिगत दिशा — भारत की जनसांख्यिकीय रणनीति को तीन स्तरों पर काम करना

होगा। पहला, मानव पूंजी-स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रासंगिक कौशल में निवेश। दूसरा, उत्पादक रोजगार-ऐसे क्षेत्रों का विस्तार जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को समाहित कर सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें। तीसरा, महिला और काम-बाल-देखभाल, आवागमन, कार्यस्थल की परिस्थितियों और कौशल जैसी बाधाओं को कम करके महिलाओं की उत्पादक भागीदारी

बढ़ाना। इसके साथ वृद्धावस्था को भी अभी से नीतिगत एजेंडे का हिस्सा बनाना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वृद्धावस्था के संदर्भ में निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थ जीवनशैली और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 'दीर्घायु लाभांश' की संभावना पर जोर देता है। अर्थात् आज की जनसांख्यिकीय नीति को एक साथ युवा नीति और वृद्धावस्था नीति दोनों होना पड़ेगा।

10. निष्कर्ष —

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर वास्तविक है। उपलब्ध अनुभवजन्य साक्ष्य यह संकेत देता है कि अनुकूल आयु-संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जनसांख्यिकीय स्वयं विकास नहीं करती; वह विकास की संभावना पैदा करती है। उस संभावना को वास्तविक लाभांश में बदलने के लिए श्रम-बाजार को कार्यशील आयु वाली आबादी को उत्पादक रोजगार में समाहित करना होगा। महिला श्रम-बल भागीदारी में सुधार, मानव पूंजी और रोजगार की गुणवत्ता इस रूपांतरण की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। इसलिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को केवल 'भारत युवा है' कहकर समझना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न है— क्या भारत अपनी युवा आबादी को समय रहते उत्पादक मानव पूंजी और उत्पादक रोजगार में बदल पाएगा? यदि उत्तर हाँ है, तो जनसांख्यिकीय संक्रमण भारत की वृद्धि-कथा का शक्तिशाली आधार बन सकता है। यदि नहीं, तो बड़ी कार्यशील आयु वाली आबादी अपने आप आर्थिक लाभांश में परिवर्तित नहीं होगी। और वृद्धावस्था की बढ़ती गति इस प्रश्न को और अधिक तात्कालिक बनाती है। इसलिए भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश न तो केवल अवसर है, न ही केवल भ्रम। वह एक अवसर है जिसकी सफलता समय, रोजगार और उत्पादकता पर निर्भर है। भारत के पास युवा भारत का लाम है; अब चुनौती है कि वह उसे उत्पादक भारत में कितनी जल्दी बदलता है।

11. उपसंहार —

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश केवल एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास-यात्रा का एक निर्णायक अवसर है। घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण भारत की आयु-संरचना में परिवर्तन हो रहा है। भारत की स्थिति को जापान के अनुभव के साथ देखने पर इस अवसर की महत्ता और अधिक स्पष्ट

होती है। जापान के सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2024 में देश की 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की आबादी कुल जनसंख्या का 29.3 प्रतिशत थी, जबकि 15-64 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी घटकर 59.6 प्रतिशत रह गई थी। इसके विपरीत, भारत अभी अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है। जापान का अनुभव यह दर्शाता है कि घटती कार्यशील आयु की आबादी और बढ़ती वृद्धावस्था दीर्घकाल में श्रम-आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक विकास पर दबाव उत्पन्न कर सकती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (2025) रोजगार परिदृश्य : जापान की रिपोर्ट भी जापान की कार्यशील आयु की आबादी में गिरावट तथा उत्पादकता और श्रम-बाजार में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालाँकि, भारत और जापान की तुलना का उद्देश्य दोनों देशों को समान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में रखना नहीं, बल्कि जापान के अनुभव से भारत के भविष्य के लिए नीतिगत सबक ग्रहण करना है। जापान के सामने आज वृद्ध आबादी के अनुभव, कौशल और कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग करने की चुनौती है, जबकि भारत के सामने अपनी विशाल युवा आबादी को मानव पूँजी और उत्पादक श्रम-शक्ति में बदलने की प्राथमिक चुनौती है। इस संदर्भ में भारत को शिक्षा की गुणवत्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार-सृजन तथा महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, जापान के अनुभव से यह भी सीखना आवश्यक है कि वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और आजीवन कौशल-विकास की तैयारी आर्थिक विकास के साथ-साथ की जानी चाहिए। भारत के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जनसांख्यिकीय लाभांश के असमान क्षेत्रीय वितरण का है। विभिन्न राज्यों की आयु-संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थितियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए एक समान राष्ट्रीय

नीति के साथ-साथ राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतियाँ भी आवश्यक हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, बाल-देखभाल सुविधाएँ, कौशल-विकास और समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, केवल रोजगार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा रोजगार की गुणवत्ता, नियमित आय, सामाजिक सुरक्षा और श्रम उत्पादकता में सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। अंततः, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश न तो अपने आप मिलने वाला आर्थिक वरदान है और न ही केवल एक भ्रम। यह एक समयबद्ध अवसर है, जिसकी सफलता नीतिगत दूरदर्शिता, संस्थागत क्षमता और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। जापान का अनुभव चेतावनी देता है कि अनुकूल जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होतीं, जबकि भारत की युवा आबादी उसे वर्तमान में विकास की एक महत्वपूर्ण संभावना प्रदान करती है। यदि भारत समय रहते मानव पूँजी में निवेश करता है, पर्याप्त एवं उत्पादक रोजगार सृजित करता है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाता है और वृद्धावस्था की चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करता है, तो वह अपनी युवा आबादी को दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि का आधार बना सकता है। अतः भारत के समक्ष वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि उसके पास युवा जनसंख्या कितनी है, बल्कि यह है कि वह इस जनसंख्या को कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता से कुशल, स्वस्थ, उत्पादक तथा आत्मनिर्भर मानव संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। यही जनसांख्यिकीय लाभांश की वास्तविक कसौटी और भारत के भावी विकास की निर्णायक शर्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography/References)

1. Aiyar, S., & Mody, A. (2011). The demographic dividend: Evidence from the Indian states (IMF Working Paper No. 11/038). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781455217885.001>
2. Ministry of Finance, Government of India. (2026). Economic survey 2025–26. Government of India. <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/>
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2026). Periodic Labour Force Survey (PLFS): Annual report, 2025. Government of India. <https://www.mospi.gov.in/>
4. United Nations Population Fund, India, & International Institute for Population Sciences. (2023). India ageing report 2023: Caring for our elders—Institutional responses. UNFPA India. <https://india.unfpa.org/en/publications/caring-our-elders-institutional-responses-india-ageing-report-2023>
5. United Nations Population Fund (UNFPA), India, & International Institute for Population Sciences (IIPS). (2023). India Ageing Report 2023: Caring for Our Elders—Institutional Responses. UNFPA India. <https://india.unfpa.org/en/publications/caring-our-elders-institutional-responses-india-ageing-report-2023>
6. Statistics Bureau of Japan. (2025). Current Population Estimates as of October 1, 2024. Ministry of Internal Affairs and Communications, Government of Japan. <https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/2024np/index.html>
7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). OECD Employment Outlook 2025: Japan. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2025-country-notes_f91531f7-en/japan_7672bd00-en.html